'गन्ना और चीनी का मूल्य तय करने की प्रणाली में सुधार की जरूरत'

साक्षात्कार

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती पैठ और सरकार के नीतिगत सुधारों के चलते घरेलू चीनी उद्योग समृद्ध हुआ है। फसल उत्पादकता में वृद्धि से गन्ना किसान भी पीछे नहीं हैं और दोनों परस्पर फल-फूल रहे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के आगामी आम बजट में चीनी से जुड़े मसलों को सुलझाने के फैसलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मिठास घुलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारण से चीनी उद्योग को ऐसी ही कई अपेक्षाएं हैं। चीनी और एथनाल के साथ गन्ना किसानों की दशा व दिशा पर इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के पूर्व प्रेसीडेंट और त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज के वाइस चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर **तरुण साहनी** से **दैनिक जागरण** के नेशनल डिप्टी ब्यूरो चीफ **सुरेंद्र प्रसाद सिंह** ने विस्तृत बातचीत की। प्रस्तुत हैं बातचीत के कुछ अंश...

275 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने के भाव के आधार पर तय हुआ था 2019 में चीनी का मूल्य

305 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंचा अब गन्ने का मूल्य जिससे चीनी तैयार करने की लागत बढ़ी

● चीनी उद्योग हमेशा सरकारी मदद की गुहार क्यों लगाता रहता है?

-गन्ना किसान और चीनी मिलें एक-दूसरे के पूरक हैं। सरकारें चीनी मिलों के कच्चे माल यानी गन्ने का भाव तय करती हैं। जबकि उससे तैयार चीनी का भाव बाजार तय करता है। गन्ना और चीनी मूल्य के बीच परस्पर उचित लिंकेज न होने से ऐसी मुश्किलें पैदा होती हैं। इसमें तत्काल सुधार की जरूरत है। रंगराजन समिति ने इसके लिए बहुत पहले सिफारिश की थी। सरकार ने कई बार इस तरह के असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया है। इसके स्थायी समाधान की जरूरत है।

● वर्ष 2019 में सरकार ने न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) घोषित किया था। क्या यह पर्याप्त नहीं है?

उस समय घोषित एमएसपी 31 रुपये प्रति किलो चीनी का भाव तत्कालीन 275 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया था। लेकिन अब गन्ना (एफआरपी) मूल्य 305 रुपये क्विंटल हो चुका है, जिससे तैयार चीनी की लागत 36 से 37 रुपये प्रति किलो हो चुकी है। लेकिन एमएसपी वहीं स्थिर है। इसमें तत्काल वृद्धि की जरूरत है। ऐसा न करने पर जहां मिलों का घाटा बढ़ेगा तो गन्ना किसानों का भुगतान रुकने से उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी।

● सीधे गन्ना रस से एथनाल बनाने की टेक्नोलाजी आने के बाद क्या कठिनाई हो रही है?

सरकार के एथनाल उत्पादन और नीतिगत फैसले से चीनी उद्योग को काफी राहत मिली है। लेकिन इस प्रक्रिया से तैयार एथनाल को और प्रोत्साहन देते हुए मूल्य 65 रुपये लीटर की जगह 69 रुपये होनी चाहिए। वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक एथनाल मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने की ओर हम बढ़ चुके हैं। सरकार के सहयोग व समर्थन की तत्काल जरूरत है।

● अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय चीनी कितनी प्रतिस्पर्धी है। निर्यात की क्या संभावनाएं है?

घरेलू चीनी मिलें वैश्विक बाजार में दूसरे देशों को कड़ी टक्कर देती हैं। हमे आगे बढ़कर इसका लाभ उठाना चाहिए। 2021-22 में घरेलू मिलों ने 1.10 करोड़ टन चीनी का रिकार्ड निर्यात किया था। लेकिन वैश्विक स्थितियों के चलते चालू सीजन के लिए केवल 60 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी गई है। इसे और बढ़ाने की सख्त जरूरत है। ऐसा न होने की दशा में घरेलू बाजार में मांग व आपूर्ति के अंतर को देखते हुए घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें लागत से नीचे आ सकती हैं, जो चीनी मिलों और गन्ना किसानों के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।

● चीनी की मांग और आपूर्ति का क्या गणित है, जिसे लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं?

चालू पेराई सीजन में एक अक्टूबर से मिलों में पेराई शुरू हुई। उस वक्त चीनी का ओपनिंग स्टाक 65 लाख टन था। जबकि चालू सीजन में 3.65 करोड़ टन चीनी उत्पादन का अनुमान है। चीनी की घरेलू खपत 2.80 करोड़ टन के करीब है। पिछले वर्ष के 1.10 करोड़ टन के मुकाबले केवल 60 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति है। कुल 45 लाख टन चीनी की जगह एथनाल का उत्पादन किया जाएगा। कम से कम 20 लाख टन सरप्लस चीनी होगी। इसलिए सरकार को चीनी निर्यात के बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।